

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अगस्त 2004—श्रावण 29, शक 1926

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2004

क्रमांक/बी-1/5/2004/1/4.—राज्य शासन, राज्य प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उनके नाम से सम्मुख कालम 4 में दर्शाये गये पदों पर पदस्थ करता है :—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री बी. एल. बंजारे (आर. आर.-89, प्र. श्रे.)	उप सचिव, ऊर्जा विभाग, रायपुर	अपर कलेक्टर, बलौदाबाजार, जिला-रायपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री एन. के. खाखा (आर. आर.-86 प्र. श्रे.)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-सरगुजा.	अपर कलेक्टर, महासमुन्द
3.	श्री एस. एल. नायक (पी-94, व. श्रे.)	पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत	संयुक्त संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति.
4.	श्री के. के. अग्रवाल (पी-94, व. श्रे.)	डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग	डिप्टी कलेक्टर, कोरिया
5.	श्री के. सी. दास (पी-92, प्र. श्रे.)	अपर कलेक्टर, महासमुन्द	अपर कलेक्टर, नारायणपुर, जिला- वस्तर.
6.	श्री एस. सी. बंजारे (पी-98, क. श्रे.)	डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग	डिप्टी कलेक्टर, महासमुन्द

2. इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 24-5-2004 के सरल क्रमांक-2 पर अंकित श्री के. एल. ग्वाल, (आर. आर.-91, प्र. श्रे.) का स्थानान्तरण अवर सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर किये जाने से संबंधित है, में आंशिक संशोधन करते हुये अब श्री ग्वाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर पदस्थ किया जाता है.

3. इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 24-5-2004 के सरल क्रमांक-5 पर अंकित श्री जे. एस. दीक्षित (पी-94, व. श्रे.) का स्थानान्तरण संयुक्त कलेक्टर, कोरिया किये जाने से संबंधित है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

4. इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 24-5-2004 के सरल क्रमांक-4 पर अंकित श्री सी. एस. डेहरे, (आर.आर.-91, व. श्रे.) का स्थानान्तरण संयुक्त कलेक्टर, बिलासपुर किये जाने से संबंधित है, में आंशिक संशोधन करते हुये अब श्री डेहरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2004

क्रमांक 3428/डी-965/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा की सदस्या श्रीमती शकुन्तला दास, अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3423/डी-965/21-ब/छ. ग./04. दिनांक 7-6-2004 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय रायपुर में पीठासीन न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

फा. क्र. 4335/डी-1747/21-ब/फास्ट ट्रेक कोर्ट/छ. ग./04.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अशोक कुमार दुबे, अधिवक्ता, अंबिकापुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट, अंबिकापुर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

फा. क्र. 4337/डी-1747/21-ब/फास्ट ट्रेक कोर्ट/छ. ग./04.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गौरांगो सिंह, अधिवक्ता अंबिकापुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट, अंबिकापुर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2004

फा. क्र. 4388/डी-1217/21-ब/फास्ट ट्रेक कोर्ट/छ. ग./04.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अखिलेश पाण्डे, अधिवक्ता को फास्ट ट्रेक कोर्ट, कोरबा में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2004

फा. क्र. 4445/1736/21-ब/छ.ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रामरेखा साहू, अधिवक्ता, कोरिया, बैकुण्ठपुर, छ. ग. को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए कोरिया, बैकुण्ठपुर के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, कोरिया, बैकुण्ठपुर, छ. ग. नियुक्त करता है।

किसी भी पक्ष द्वारा एक मूह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2004

क्रमांक 568/F-2-16/32/04.—छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा धर्मजयगढ़ नगर निवेश क्षेत्र का गठन करता है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं :—

अनुसूची

धर्मजयगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर	-	ग्राम सेमीपाली खुर्द, गेवरघुटरी एवं ग्राम अमली टिकरा की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम	-	ग्राम अमली टिकरा, शाहपुर एवं ग्राम तराईमार की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण	-	ग्राम तराईमार, मेढ़रभाटा, दरीडीह एवं ओमना की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व	-	ग्राम ओमना, मढ़रीमुडा, धर्मजयगढ़ एवं ग्राम सेमीपाली खुर्द की पूर्वी सीमा तक.

धर्मजयगढ़ निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या से संबंधित जानकारी

क्रमांक (1)	शहर ग्राम का नाम (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)	जनसंख्या 1991 (4)
1.	अमली टिकरा	1673.61	1431
2.	गेवरघुटरी	566.11	439
3.	सेमीपाली खुर्द	99.62	173
4.	शाहपुर	448.28	748
5.	तराईमार	358.71	307
6.	मेढ़रभाटा	156.54	171
7.	दरीडीह	630.64	779
8.	ओमना	1222.71	1005
9.	मढ़रीमुडा	35.48	197
योग (अ)		5191.70 हे.	5250
10.	धर्मजयगढ़ (नगरपालिका का क्षेत्र)	योग (ब) 3124.00 हे.	11000
कुल योग (अ+ब)		8315.70 हे.	16250

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2004

क्रमांक 856/566/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा अड़भार नगर पंचायत के निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दर्शायी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं।

अनुसूची

अड़भार निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर	-	ग्राम दिमानी, बड़भार एवं हरदी की उत्तरी सीमा तक
पूर्व	-	ग्राम हरदी, बंजारी, संजारी एवं चरौदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण	-	ग्राम चरौदा एवं बंदौरा एवं बुंदेली की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम	-	ग्राम बंदौरा, बुंदेली एवं दिमानी की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक 996/584/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन के सूचना क्रमांक 552/584/32/04 दिनांक 21-5-2004 द्वारा विकास योजना भिलाई-दुर्ग भाग-2 में उपान्तरण प्रस्तावित किये गये थे जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी, प्रकाशित सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अतः राज्य सरकार एतद्वारा ग्राम कातुलबोर्ड के खसरा नं. 3/33 नया 3/237 एवं 3/338 रकबा 0.486 हेक्टेयर की सूचना में किये गये उल्लेख अनुसार विकास योजना भिलाई-दुर्ग भाग-2, दुर्ग 2001 के निर्धारित आवासीय से कृषि उपयोग में उपान्तरण करने की पुष्टि करती है तथा सूचित करती है कि वह उपान्तरण भिलाई-दुर्ग भाग-दो, दुर्ग विकास योजना 2001 का एकीकृत भाग होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर, (पंजीयन) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 6/316/2002/वाक./पांच.—राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती रीना वर्मा, जिला पंजीयक, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में अनुसंधान अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं की सेवायें वापस लेते हुये उन्हें, उप महानिरीक्षक पंजीयन के पद पर वेतनमान 10,000-325-15,200 में पदोन्नत कर, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कार्यालय

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़, रायपुर में उप महानिरीक्षक पंजीयन के रिक्त पद पर पदस्थ करता है।

2. (i) पदोन्नत अधिकारी को आदेश प्राप्ति की तारीख से एक माह के अंदर सक्षम अधिकारी को यह विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि—

(क) जिला पंजीयक के पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद आगे कोई पुनरीक्षण किये बिना सीधे ही मूल नियम 22-डी के अंतर्गत उप महानिरीक्षक पंजीयन के पद में उसका प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया जावे।

अथवा

(ख) उप महानिरीक्षक पंजीयन के पद पर (पहली बार) उसका वेतन मूल नियम 22-ए (1) में दिये गये तरीके से निर्धारित किया जाये और दूसरी बार जिला पंजीयक के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उसी तारीख को उसका वेतन मूल नियम 22-डी के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण किया जाये।

(ii) यदि अधिकारी द्वारा उपर्युक्त विकल्पों में से विकल्प (ख) अपनाया जाता है तो उसकी आगामी वेतनवृद्धि, दूसरी बार वेतन निर्धारण की तारीख से 12 माह की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने की तारीख को देय होगी।

(iii) इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प अपनाने पर अधिकारी को मूल नियम 22-डी (2) के प्रावधानों अनुसार नियम 22 के परन्तुक का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा एवं एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

(iv) उक्त पदोन्नति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जून 2004

क्रमांक एफ-16-13-11-वा.उ./2001.—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि जनहित में तथा श्रमिक वर्ग के हित में मेसर्स अम्बूजा सीमेंट ईस्टर्न लि. (पूर्व नाम मोदी सीमेंट लि.) रायपुर को सहायता उपक्रम घोषित करना आवश्यक है।

2. अतएव छत्तीसगढ़ सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1978 (क्रमांक 32 सन् 1978) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा औद्योगिक इकाई अर्थात् "मेसर्स अम्बूजा सीमेंट ईस्टर्न लि. (पूर्व नाम मोदी सीमेंट लि.) रायपुर" को दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक की अवधि के लिए सहायता उपक्रम घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव।

रायपुर, दिनांक 18 जून 2004

क्रमांक एफ-16-13-11-वा.उ./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-13-11-वा. उ./2001 दिनांक 18-6-2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव.

Raipur, the 18th June 2004

No. F-16-13-11/2001.—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary in the Public Interest and in the interest of workers to declare the Industrial Unit, namely M/s Ambuja Cement Eastern Ltd.. (formerly Modi Cement Ltd.) Raipur, a relief undertaking.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provision to Section 3 of the Chhattisgarh Sahayata Upkram (Vishesh Uphandh) Sansodhan Adhiniyam 1978 (No. 32 of 1978) the State Government hereby declare the Industrial Unit namely "M/s AMBUJA CEMENT EASTERN LTD.. (formerly Modi Cement Ltd.) Raipur" a relief undertaking for the period with effect from 1st April, 2003 to 31st March, 2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
G. D. GUPTA, Deputy Secretary.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2004

क्रमांक एफ 1-35/2004/13-1.—राज्य शासन एतद्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 89 की उपधारा (2) एवं (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 288/ऊ. वि./वि.क.अ./2003 दिनांक 23-8-2003 एवं 403/स/ऊ.वि./2003 दिनांक 1-10-2003 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें नियम 2003" के नियम (2) एवं नियम (10) के स्थान पर निम्नानुसार नियम प्रतिस्थापित करता है :—

(2) आवास सुविधा :—

- (अ) अध्यक्ष एवं सदस्य को आवास की सुविधा राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी को प्राप्त आवास सुविधा के अनुरूप होगी.
- (ब) आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं सदस्य को अधिकतम रुपये 50,000/- तक की आवास की साज-सज्जा की पात्रता होगी. आगामी अध्यक्ष एवं सदस्य को अधिकतम रुपये 10,000/-तक साज-सज्जा की पात्रता होगी.
- (स) अध्यक्ष एवं सदस्य को निवासीय कार्यालय की पात्रता होगी.

(10) दूरभाष व अतिथि सत्कार सुविधा :—

- (अ) दूरभाष :—अध्यक्ष एवं सदस्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारियों को प्राप्त सुविधा के अनुरूप दूरभाष की सुविधा प्राप्त होगी.
- (ब) अतिथि सत्कार भत्ता :—अध्यक्ष के लिए रुपये 6,000/- प्रतिमाह तथा सदस्य के लिए रुपये 4,000/- प्रतिमाह अतिथि सत्कार भत्ता देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, विशेष सचिव

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 अप्रैल 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 26/अ-82/सन् 2003-2004. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लोहाखान प. ह. नं. 34	0.411	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़.	लोहाखान जलाशय हेतु पुरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 597 /अ-82/सन् 2003-2004. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	छोटे अतरमुड़ा प. ह. नं. 13	0.619	कार्यपालन यंत्री, छ. ग. गृह निर्माण मंडल, संभाग बिलासपुर.	छ. ग. गृह निर्माण मंडल की आवासीय कालोनी निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 23 जून 2004

क्रमांक/222/अ.वि.अ./भू-अर्जन/15 अ/82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	पड़कीपाली प. ह. नं. 118/65	0.12	कार्यपालन अभियंता, कोडार परियोजना, संभाग महासमुन्द	चंडी डोंगरी जलाशय योजना के अंतर्गत पड़कीपाली माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2004

क्रमांक 3773/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	विचारपुर प. ह. नं. 18	0.19	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत विचारपुर माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2004

क्रमांक 3774/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	चम्पाटोला प. ह. नं. 4	6.66	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	चम्पाटोला टार बांध के अंतर्गत बांध पार एवं डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2004

क्रमांक 3775/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	गरा प. ह. नं. 15	0.97	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	मानीकचौरी डायवर्सन के अंतर्गत गरा माडनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2004

क्रमांक 3776/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	शिकारीटोला प. ह. नं. 10	3.49	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	सिरसाही टारवांध के इयान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 जुलाई 2004

क्रमांक 4572/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	जोरातराई प. ह. नं. 28	10.51	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, जिला दुर्ग.	रींदा जलाशय के अंतर्गत यांध पार एवं इयान.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 20 मई 2004

रा. प्र. क्र. 2/अ 82/2003-2004. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	खूंटापारा	0.35	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, अंबिकापुर.	डुमरिया-गंगोटी मार्ग पर गोबरी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 मई 2004

रा. प्र. क्र. 3/अ 82/2003-2004. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	मोहरसोप	0.51	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, अंबिकापुर.	ओडगी-बिहारपुर मार्ग पर बरंगा सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 11 अगस्त 2004

क्रमांक 423/ले.पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को उसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	पथरिया	0.09	कार्यपालन यंत्रों, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	शिवनाथ नदी सेतु पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 अगस्त 2004

क्रमांक 426/ले.पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को उसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	चंगोरी	0.17	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	अंजोरा-चंगोरी मार्ग पर चंगोरी नाला सेतु निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 6 मई 2004

क्रमांक 142/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा उक्त आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	चोपन	1.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर.	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बांध का निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 14 मई 2004

क्रमांक 769/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/04/अ/82-03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	धुमरापदर	11.78	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग गरियाबंद.	धुमरापदर जलाशय योजना के अंतर्गत उलट नाली निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

विलासपुर दिनांक 1 जुलाई 2004

અનુસૂચી

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	लूफा	0.117	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड.	चूना खोंदरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिलासपुर दिनांक 1 जुलाई 2004

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बेहरामुड़ा	1.493	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड.	सेन्दरी पानी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिलासपुर दिनांक 1 जुलाई 2004

प्रकरण क्र. 8 अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पंचरा	15.765	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड.	चांदी जलाशय डूबान हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर दिनांक 1 जुलाई 2004

प्रकरण क्र. 9 अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बांसाझाल	2.863	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड.	चांदी जलाशय के डूबान हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 अगस्त 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/3.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बम्हनी प.ह.नं. 19	0.206	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, चांपा, संभाग चांपा.	बम्हनी करनई देवरी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 जुलाई 2004

रा. प्र. क्रमांक 01/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6-के. अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-लोरमी

(ग) नगर/ग्राम-गुनापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-43.50 एकड़

खसरा नम्बर

रकबा
(एकड़ में)

(1)

(2)

9/1 ढ

1.60

(1)

(2)

9/1 भ

0.15

9/1 फ

1.00

9/1 ड

2.00

9/1 प

1.00

9/10 ध

3.00

9/10 फ

3.00

9/10 थ

1.90

9/1 ण

1.34

63/1

3.00

63/3

0.72

9/1 घ

2.76

68

0.40

71

0.85

53/3

1.04

53/2

3.50

52/2

0.10

(1)

(2)

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

51/2

0.66

9/1 ग, 9/1 ड

0.78

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2004

9/1 ल, 9/1 व

2.10

9/1 म, 9/1 र

2.33

9/1 अ

0.50

9/1 ब

0.43

9/1 म

0.31

9/25

0.02

9/31

0.36

9/36

0.10

9/39

0.18

9/1 ख

1.00

9/10 झ

0.81

9/22

0.40

9/58

0.16

9/10 न

3.00

69/3

3.00

योग

32

43.50

क्रमांक/क/भू-अर्जन/29-अ/82, 2001-2002. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क.) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-करवाड़वरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.976 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

7/1

0.008

4

0.016

5

0.036

7/3

0.028

7/5

0.008

8

0.020

9/1

0.024

11/2

0.020

12/1

0.024

15,16

0.036

209/1

0.036

211

0.024

212

0.024

213/2

0.044

214

0.008

215/1

0.016

215/2

0.020

216/1

0.012

216/2

0.016

217

0.068

281/1

0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भरत सागर
जलाशय के (डूबान) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लोरमी के कार्यालय में देखा
जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

(1)	(2)
281/5	0.032
281/4	0.024
281/3	0.032
281/2	0.024
281/6	0.040
280	0.117
279	0.060
275/2	0.016
278/1	0.020
276	0.032
277	0.008
297	0.036
298/5	0.008
298/2	0.048
306	0.060
308/2	0.032
308/1	0.008
309/1	0.028
309/2	0.008
252/2	0.064
331/2	0.061
331/3	0.036
333	0.024
345/1	0.032
344/1	0.032
341/2	0.012
350	0.028
349/1	0.044
349/2	0.008
351	0.008
354/1	0.040
353	0.064
366/1	0.028
366/2	0.024
371/11	0.016
371/1	0.069
377/2	0.040
377/1	0.012
374	0.024
365	0.020
373/1	0.012
372/1	0.008

(1)	(2)
411/5 घ	0.073
411/5 ग	0.032
352/1	0.008
योग	64
	1.976

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—करवा-
डवरी माइनर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी,
बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक/क/भू-अर्जन/30-अ/82, 2001-2002. —चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.714 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
344/4	0.040
344/6	0.061
344/7	0.038
342/2	0.088
342/1	0.064
206/3	0.088
206/6	0.040
206/4	0.077
210	0.068
198/2	0.053
198/4	0.040

(1)

(2)

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2004

197	0.139
190/1	0.056
190/3	0.061
188/2	0.032
188/1	0.084
180	0.040
178	0.040
224/1	0.028
159/3	0.032
159/2	0.036
157	0.028
156	0.038
152/3	0.008
154	0.056
153	0.024
121/2	0.032
126/3	0.072
126/2	0.049
126/1	0.024
124/1-2	0.024
123/1	0.032
189	0.004
111	0.016
110	0.008
108/6	0.016
11/1	0.037
11/4	0.032
108/3	0.016
10/1	0.056
89	0.012
88/5	0.012
112	0.016
90/2	0.016
90/1	0.318
92/1	0.418
92/2	0.008
116/1	0.008
95	0.032
91	0.008
26	0.081
187	0.008

योग	54	2.714
-----	----	-------

क्रमांक/क/भू-अर्जन/31-अ/82, 2001-2002. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-विलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-रमतला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.336 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

134/1, 138/1 ख

0.024

360/3

0.016

360/4

0.024

174/3 ग, 360/1

0.024

358, 359

0.061

357/12

0.028

357/2

0.024

357/3

0.036

357/4

0.016

348/1

0.004

349/1

0.016

351/1

0.040

357/5

0.020

344/1

0.044

342/1

0.008

342/4

0.016

341/2

0.008

341/1

0.008

340/1

0.036

340/2

0.012

337, 338, 339

0.024

336

0.016

469

0.008

472/3

0.008

473/2

0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रामपुर माइनर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, विलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

(1)

(2)

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2004

468/4	0.016
475	0.016
468/2	0.016
476, 477	0.016
468/3	0.044
457/1	0.016
457/2	0.024
456/1	0.032
455	0.012
482/1-2	0.020
481	0.020
497/1	0.036
491/2	0.036
495	0.040
494/1	0.048
624/1	0.036
624/2	0.032
624/3	0.020
565	0.024
564	0.004
566/2, 569/2	0.012
566/1, 569/1	0.036
568/2	0.032
574/1	0.032
576/1	0.036
576/2	0.044
573	0.004
577	0.032
582	0.012
547/2	0.036
583/3	0.012
547/1	0.056
547/3	0.044
547/4	0.061
547/8	0.030
138/1 च, 138/1 क	0.101
138/6	0.020
138/5 क	0.477
164	0.020
84	0.186

योग 65 2.336

क्रमांक/क/भू-अर्जन/32-अ/82, 2001-2002. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दो गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-रमतला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.571 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

154/3	0.024
154/1	0.020
156/1	0.048
156/2	0.032
155/1	0.041
240/3	0.024
240/1	0.028
240/4-5	0.072
249/4	0.049
249/3	0.028
250	0.036
219	0.008
216/2	0.032
216/3	0.032
213/2	0.032
212	0.021
211/3	0.061
277/1	0.012
278	0.061
279	0.044
714	0.081
713	0.093
712	0.004
711	0.012
655	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-
टाडापारा माइनर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी,
बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1)	(2)	(1) भूमि का वर्णन-	
662	0.052	(क) जिला-रायपुर	
664/3	0.028	(ख) तहसील-बिलाईगढ़	
665/1	0.016	(ग) नगर/ग्राम-खजरी	
673	0.044	(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.524 हेक्टेयर	
672/2	0.068	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
672/1	0.021	(1)	(2)
678/2	0.032		
678/1	0.004	268/5	0.068
683/1	0.024	268/3	0.016
683/2	0.044	268/2	0.064
686/2	0.008	268/4	0.072
687	0.008	269/2	0.008
690	0.024	269/5	0.073
684	0.048	270/2	0.053
665/2	0.028	271/2	0.073
138/7	0.021	270/1	0.052
151/1	0.028	275/1	0.012
150	0.028	265/2	0.068
138/8 क	0.094	265/3	0.056
208	0.044	264/1	0.088
		262/3	0.016
		262/1	0.032
		263/2	0.028
		79/1 थ	0.056
योग	45	79/1 द	0.198
	1.571	79/1 घ	0.081
		79/1 न	0.169
		271/1	0.096
		79/1 प	0.016
		79/1 र	0.012
		25/2	0.012
		25/1	0.021
		26/3	0.060
		26/1	0.021
		27/1	0.077
		27/3	0.012
		28	0.036
		31/8	0.064
		31/4	0.137
		31/9	0.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रमतला
माइनर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी,
बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक/क/भू-अर्जन/33-अ/82, 2001-2002. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

(1)	(2)	(1)	(2)
31/5	0.021	84/3	0.016
34	0.093	168/4	0.012
9	0.129	168/3	0.020
10/2	0.068	168/2	0.020
3/2	0.098	168/1	0.012
3/3	0.021	159/1	0.121
3/1	0.021	159/2	0.053
4/2	0.061	159/3	0.024
79/8 घ	0.088		
योग	41	167, 327, 328	0.016
	2.524		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.		329	0.137
		379/2	0.056
		379/1	0.084
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.		496/1	0.064
		375/1	0.024
		375/3	0.020
		375/4	0.048
रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2004		373/2	0.028
क्रमांक/क/भू-अर्जन/34-अ/82, 2001-2002. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		373/1	0.028
		373/3	0.020
		509	0.093
		510	0.052
		369/1	0.056
अनुसूची		511/2	0.056
(1) भूमि का वर्णन-		511/3	0.129
(क) जिला-रायपुर		513/1-2, 514/1-2	0.012
(ख) तहसील-बिलाईगढ़		515/1-2	0.105
(ग) नगर/ग्राम-भण्डोरा		518	0.113
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.090 हेक्टेयर		519/1	0.084
खसरा नम्बर	रकबा	519/3	0.032
(1)	(हेक्टेयर में)	520	0.093
	(2)	626	0.093
92/1	0.056	625	0.121
92/5	0.048	522	0.109
93/2	0.069	622	0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
526/4	0.020	175	0.129
527/2	0.044	382	0.121
527/1	0.061	323	0.105
614/1	0.012		
614/5	0.084	योग	54
166	0.028		3.090
613/1	0.081		
607/3	0.101	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-भण्डारा माइनर निर्माण कार्य हेतु.	
607/2	0.016		
608/2	0.008	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
605	0.016		
606	0.068		
599/2	0.008	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.	
601/1	0.036		

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिलासपुर (छ. ग.)

“प्रारूप-ख”

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 24 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	उसलापुर/35	17	3.78

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 25 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदोविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए।

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	दवनडीह/36	41	12.17

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 26 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदोविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए।

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	कर्ग/36	21	8.74

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 27 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के संबंध में, संक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	धनियां/35	06	1.60

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 28 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के संबंध में, संक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	कुली/34	50	17.95

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 29 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदोविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकार, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	खम्हरियां/34	55	22.66

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 30 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदोविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकार, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	परसाही/36	16	7.16

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 31 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	लुतरा/34	24	7.28

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 32 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	भौराडीह/34	24	7.08

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 33 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सोपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मंसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकार, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	खांडा/35	35	9.56

ए. के. तिवारी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

“प्रारूप-ख”

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक 04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सुलताननार, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा तक मेसर्स एनटोपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	कोरबी/22	46	14.22

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक 05.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सुलताननार, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा तक मेसर्स एनटोपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	सुलताननार/20	50	17.43

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक 06.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सुलताननार, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	डोंगरी/22	48	15.12

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक 07.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सुलताननार, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बलौदा/21	128	36.44

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक 08.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सुलताननार, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	हरदीविशाल/23	6	2.85

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक 09.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सुलताननार, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	चारपारा/20	24	9.63

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक 10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सुलताननार, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	भिलाई/22	59	12.46

ए. लकड़ा,
अनुविभागीय अधिकारी.

